बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र07–विविध–25 / 2018 4010 खाद्य, पटना / दिनांक– 20.8.18

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– **जिला स्तर से दिनांक 16.08.2018 को राज्य स्तर द्वारा निर्धारित पंचायतों के जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण करने एवं निरीक्षण के पश्चात् Action Taken Report (ATR) POIMS पर अपलोड करने एवं प्राप्त Action Taken Report (ATR) के विरूद्ध कार्रवाई करने से सम्बन्धित प्रतिवेदन भेजने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार, पटना के निदेश के आलोक में दिनांक 16.08.2018 को जिला स्तर पर जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी / प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक के द्वारा किया गया है। सम्बन्धित प्रतिवेदन उसी दिन POIMS पर अपलोड करने हेतु पूर्व में निदेशित किया जा चुका है।

उक्त प्रतिवेदन के आधार पर Action taken Report अभी तक विभाग को अप्राप्त है। जिन प्रखंड / पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध अनियमितता की गंभीर शिकायत पायी गयी है, उनके विरूद्ध बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत त्वरित कार्रवाई करने की कृपा की जाय। साथ ही कृत कार्रवाई से विभाग को संसूचित करते हुए Action taken Report विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर निम्नांकित सारणी में भेजने की कृपा की जाय ।

क्र0	जिला का नाम	निरीक्षण किये गये पंचायतों की संख्या	निरीक्षण किये गये जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	अनियमितता पाये गये जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	कार्रवाई / रद्द किये गये जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

विश्वासभाजन,

20/8/2018

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–विविध– 25 / 2018 4010 खाद्य, पटना / दिनांक– 20.8.18

प्रतिलिपि – सभी उप निदेशक (खाद्य) / अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना / विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/8/2018

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–विविध– 25 / 2018 4010 खाद्य, पटना / दिनांक– 20.8.18

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20/8/2018

सरकार के सचिव।

D:\M_2016\Sec_7\Inspection.doc